

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 3) मार्च, 2016।

विषय:- जनपद चम्पावत में इन्टीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान (जी०एन०एम०+ बी०एस०सी० नर्सिंग) के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि पी०एल०ए० में रखें जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 26प/चि०शि०/64/2012/1761 दिनांक 20 नवम्बर 2015 के द्वारा उपलब्ध कराये गये डी०पी०आर० में टी०ए०सी०, वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि (निर्माण कार्यों हेतु रू० 2210.86 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत रू० 151.47 लाख) इस प्रकार कुल रू० 2362.33 लाख की वित्तीय एव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू० 3,00,00,000/- (रू० तीन करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में से अवमुक्त कर निदेशक चिकित्सा शिक्षा के पी०एल०ए० में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- iii. पी०एल०ए० से धनराशि का आहरण आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा पी०एल०ए० से आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
- iv. योजना में निर्मित किये गये संस्थान के स्थल विकास कार्य की लागत रू० 285.00 लाख अत्यधिक प्रतीत हो रही है। वास्तविक कार्य कराते समय इसका पुनः परीक्षण किया जाय एवं स्थल की दशा के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- v. प्रश्नगत संस्थान नर्सिंग के प्रशिक्षण से संबंधित है। अतः आगणन में इस प्रकार का कोई भी प्राविधान न किया जाय जो मरीजों के उपयोग के लिए हो एवं ऐसी मदें सम्मिलित न किये जाय जो अनावश्यक रूप से आगणन की लागत में वृद्धि कर रही हो, जैसे- सामान्य लिफ्ट का प्राविधान किया जाय और मरीजों से संबंधित लिफ्ट का प्राविधान न हो।
- vi. आगणन में कन्टीजेन्सी मद में केवल 2 प्रतिशत धनराशि देय होगी। कार्य 18 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात् कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

- 5198
- vii. वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवन को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु buildings के संबंध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय। तथा इस संबंध में Tata Energy Research Institute (TERI) द्वारा जारी Guide line/Representative designs of energy का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
- viii. सौर उर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा— सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।
- ix. Water harvesting का समुचित प्राविधान किया जाय।
- x. निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L.Laboratory से परीक्षण करा लिया जाय।
- xi. Electrical Items जैसे switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings geyser, water tank, pipes आदि Toilet items, wood items आदि की Market Survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निदेशक चिकित्सा शिक्षा के साथ समन्वय कर पूर्व में ही Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मदों की लागत रू0 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली-2008 (यथासंशोधित 2015) के अनुसार की जाय।
- xii. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं, उदाहरणार्थ—वाटरप्रूफिंग की मदें अलग से आगणन में ली गई हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृता

*Handwritten signature*

अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।

- xiii. आगणन में प्राविधानित सोक पिट तथा सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडाजेस्टर आधारित ट्रीटमेंट का प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।
- xiv. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से अवश्य लें।
- xv. कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम) अपने कार्य प्रदर्शिका, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा डी0एस0आर0 के नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि त्रुटिवश कोई फाइनेंशियल डुप्लीकेसी होती है, तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे।
- xvi. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xvii. उक्त कार्य को निर्धारित लागत एवं निर्धारित समय में पूर्ण करने का नियमानुरूप अनुबन्ध (MOU) कार्यदायी संस्था के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा करके एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- xviii. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- xix. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि आगणन में स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- xx. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- xxi. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।



- xxii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- xxiii. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- xxiv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219/2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- xxv. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किये जा सकेंगे।
- xxvi. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है। भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है।
- xxvii. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- xxviii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 13-नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी) 24-वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।



4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-452 (P)/XXVII(3)/2016 दिनांक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5— उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर आई0डी0 स्वीकृति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।


भवदीय,

(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-262/XXVIII(1)/2016- 11 (नर्सिंग) /2014 तददिनांक

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायू मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम नेहरू कालोनी, देहरादून।
- 7- बजट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(शिव शंकर मिश्रा)  
अनु सचिव।